भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1661
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

इंटरनेट तक पहुंच नहीं होने के कारण डिजिटल भुगतान में बाधा

1661. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इंटरनेट की पहुंच का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट तक पहुंच नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान में बाधा आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में 969.10 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं जिनमें देश के ग्रामीण क्षेत्र से 407.69 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता शामिल हैं। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-क में है।

(ग) देश में डिजिटल भुगतान से लेनदेन की कुल राशि वित्त वर्ष 2017-18 में 2071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 22,831 करोड़ हो गई है जो 41% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रही है।

(घ) सरकार 4जी सैचुरेशन परियोजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को मांग के आधार पर वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि जैसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करना है।

अनुबंध-क

लोक सभा के दिनांक 30.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1661 के भाग (क) एवं (ख) में उल्लिखित अनुबंध-क

मार्च 2025 के समाप्ति पर प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट उपभोक्ताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या				
क्र. सं.	राज्य	कुल उपभोक्ता (मिलियन में)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	17.98	18.49	36.47
2	अरुणाचल प्रदेश	0.54	0.39	0.93
3	असम	13.38	6.95	20.33
4	बिहार	37.57	16.80	54.37
5	छत्तीसगढ	8.55	8.96	17.51
6	गोवा	0.63	1.78	2.41
7	गुजरात	19.18	36.67	55.86
8	हरियाणा	10.11	20.02	30.14
9	हिमाचल प्रदेश	4	2.67	6.67
10	झारखंड	10.94	8.43	19.37
11	कर्नाटक	21.47	38.83	60.30
12	केरल	18.22	17.84	36.06
13	मध्य प्रदेश	21.13	28.36	49.50
14	महाराष्ट्र	32.84	76.62	109.46
15	मणिपुर	0.98	1.32	2.30
16	मेघालय	1.34	0.75	2.08
17	मिजोरम	0.54	0.70	1.24
18	नागालैंड	0.98	0.68	1.66
19	ओडिशा	17.10	8.78	25.89
20	पंजाब	9.60	17.59	27.19
21	राजस्थान	26.07	25.97	52.04
22	सिक्किम	0.37	0.27	0.64
23	तमिलनाडु	18.01	45.47	63.48
24	तेलंगाना	13.08	23.11	36.19

25	त्रिपुरा	1.07	1.13	2.19
26	उत्तर प्रदेश	65.41	65.72	131.14
27	उत्तराखंड	4.81	5.05	9.86
28	पश्चिम बंगाल	25.61	38.13	63.75
संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.23	0.21	0.43
30	चंडीगढ़	0.03	1.36	1.39
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.30	0.55	0.84
32	दिल्ली	0.31	35.56	35.88
33	जम्मू और कश्मीर	4.58	5.34	9.92
34	लद्दाख	0.32	0.11	0.43
35	लक्षद्वीप	0.05	0.004	0.05
36	पुडुचेरी	0.36	0.79	1.15
	कुल	407.69	561.42	969.10

****